प्रधानमंत्री 4 जुलाई को आएंगे, मुख्यमंत्री तैयारी में जुटे

वे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन तथा जयपुर मैट्रो फेज़-2 का शिलान्यास करेंगे

जयपुर, 24 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 4 जुलाई की राजस्थान यात्रा की तैयारी में जुट गये हैं। आज मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों बैठक ली। रिफाइनरी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को रिफाइनरी का मॉडल भेंट किया व परियोजना की प्रगति व संचालन की

- **रिफाइनरी प्रबंधन ने मुख्यमंत्री की माइक्रो मॉनिटरिंग की सराहना की। उन्होंने कहा कि सतत मार्गदर्शन व प्रोत्साहन के कारण सही समय के अंतराल में रिफाइनरी संचालन के लिए पुनः तैयार हो गई। आधा दर्जन यूनिट कार्य कर रहे हैं।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों बैठक ली। इस अवसर पर रिफाइनरी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को रिफाइनरी का मॉडल भेंट किया।

विस्तृत जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा आएंगे। इस अवसर पर पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन एवं जयपुर मेट्रो फेज-2 के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री प्रदेशभर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास की सौगात देंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त करना प्रत्येक युवा के जीवन का गौरवपूर्ण क्षण होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में विशेष आयोजन के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं एवं आमजन को प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि वे इस ऐतिहासिक अवसर के सहभागी बन सकें।

उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन तथा रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने निर्देश दिए कि रिफाइनरी परिसर में सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री को एचआरआरएल प्रबंधन ने पचपदरा रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न प्रोडक्ट्स के सैम्पल भेंट किए। साथ ही, उन्होंने रिफाइनरी का मॉडल और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाती हुई बुकलेट भी प्रस्तुत की।

इस दौरान एचआरआरएल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री की माइक्रो मॉनिटरिंग की सराहना की। उन्होंने कहा कि एचआरआरएल एवं राज्य सरकार के अधिकारियों ने टीम भावना से निरंतर कार्य किया है। मुख्यमंत्री के सतत् मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के फलस्वरूप कुछ ही समय के अंतराल में रिफाइनरी संचालन के लिए पुनः तैयार हो गई है। आधा दर्जन से अधिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं और कई प्रोडक्ट्स का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित एचआरआरएल एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, एचपीसीएल एवं विभिन्न जिलों से संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़ें।

अरुणाचल में बाढ़ से पांच जिलों का सम्पर्क कटा

इटानगर, 24 जून। अरुणाचल प्रदेश के केयी पान्योर ज़िले में पोसा के नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निपको) प्रोजेक्ट की कॉलोनी के आस-पास के इलाकों में बीती रात से बुधवार सुबह तक लगातार हुई भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गयी तथा क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ के संबंध में दी गयी जानकारी के अनुसार, आज दोपहर

- **नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की कॉलोनी में 20 क्वाटरों को भारी क्षति पहुंची**

अचानक आई बाढ़ के चलते 3 बजे तक पांच लोग लापता हैं। निपको प्रोजेक्ट हेड के अनुसार, पांच लोगों के लापता होने की सूचना है। इस बीच कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को एम्बुलेंस से ज़ीरो ले जाया गया है।

मानवाधिकार आयोग ने युवती के झुलसने का प्रसंज्ञान लिया

जगतपुरा में पुलिस द्वारा ठेला पलटने के कारण खौलते पानी से पीड़िता गंभीर रूप से जल गई थी

- **मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, कलैक्टर तथा डीसीपी पूर्व से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, ताकि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जा सके।**

जयपुर, 24 जून। राज्य मानवाधिकार आयोग ने जगतपुरा के महल रोड इलाके में वीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस कार्रवाई के दौरान, फास्ट फूड विक्रेता युवती के झुलसने की घटना को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही आयोग ने मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और डीसीपी पूर्व से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने ये आदेश घटना के संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए दिए।

आयोग ने संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हुए कहा है कि यदि घटना में कोई लोक सेवक जिम्मेदार मिले तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के साथ ही प्राथमिकी दर्ज कराने की स्थिति भी स्पष्ट की जाए। साथ ही, पीड़िता को चिकित्सा सुविधा व मुआवजा देना भी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, आयोग ने प्रशासन को कहा है कि सभी पुलिसकर्मियों व लोक सेवकों को आमजन के प्रति संवेदनशील व मानवीय व्यवहार सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि बीएससी डिग्रीधारी रेशु की नौकरी न होने के कारण वह पिछले कुछ समय से वहां पर मोमोज का ठेला लगाकर अपनी बहनों का पालन-पोषण कर रही थी।

घटना के दिन वीआईपी काफिले के कारण पुलिस ने उसका ठेला पलट दिया, जिससे खौलता पानी उस पर गिरने से वह गंभीर रूप से जल गई। अस्पताल से लौटने के बाद, युवती अपनी बहन के साथ रामनगरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस में दखल नहीं देगा

अदालत ने कहा कि कोई यह मांग नहीं कर सकता कि प्राइवेट संस्थान सरकारी संस्थानों के बराबर फीस वसूलें

- **राजस्थान के एक मेडिकल छात्र की याचिका थी कि राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस 18-20 लाख से 25 लाख के बीच है, जो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा के बिल्कुल विपरीत है।**

नई दिल्ली, 24 जून। चिकित्सा शिक्षा का सपना देखने वाले युवाओं के संघर्ष और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े संदेश सामने आए हैं।

देश में डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा शिक्षा की सुलभता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद मानवीय और व्यावहारिक रुख अपनाया है। एक तरफ जहां कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कालेजों की फीस तय करने में दखल देने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ, सरकारी सेवा में कार्यरत डाक्टरों की विशेषज्ञता को जनहित के लिए अनमोल बताया।

कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस बहुत ज्यादा है।

राजस्थान के एक मेडिकल छात्र ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस 18.90 लाख से 25 लाख रुपये के बीच है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा के बिल्कुल विपरीत है।

ऐसे में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कोई मेधावी छात्र डॉक्टर कैसे बनेगा? याचिकाकर्ता छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी)-2025 में शामिल हुआ था।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस दर्द को समझा, लेकिन व्यावहारिक पक्ष रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा, हमें इस देश में डॉक्टरों की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति यह मांग नहीं कर सकता कि स्व-वित्तपोषित (प्राइवेट) संस्थान भी सरकारी संस्थानों के बराबर ही फीस वसूलें।

कोर्ट ने छात्र को याद दिलाया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) का विकल्प हमेशा खुला रहता है। इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इन्कार कर दिया।

इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने तमिलनाडु का एक और संवेदनशील मामला आया। तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर मांग की थी कि शैक्षिणक वर्ष 2025-2026 के लिए खाली रह गईं 152 इन-सर्विस सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों को अखिल भारतीय कोटा में सरेंडर करने से रोका जाए। इस मामले पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया और केंद्र एवं तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया।

दुविधा में फंसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी की ईरान की आखिरी आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा मई 2016 में हुई थी। उस दौरान उन्होंने खामेनेई और तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की थी और चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दो वर्ष बाद, फरवरी 2018 में राष्ट्रपति रूहानी प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आए थे और नई दिल्ली तथा हैदराबाद का दौरा किया था। मोदी और पेज़ेश्कियन की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेज़ेश्कियन को भारत आने का निमंत्रण दिया था। नई दिल्ली के सूत्रों का कहना है कि भारत ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इस राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। वर्ष 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेहरान गए थे। उन्होंने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आधिकारिक श्रद्धांजलि और शोक समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शोक संदेश व्यक्त किया था। भारत ने 21 मई 2024 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की थी। भारत ने 5 मार्च को औपचारिक रूप से खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया था। विदेश सचिव विक्रम मिसरी नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास गए थे और उन्होंने वहाँ आधिकारिक शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे।

कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी, 4 की मौत

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का अनुमान है कि 30 से अधिक मजदूर मलबे में फंसे हैं

कोलकाता, 24 जून। कोलकाता के तारातला इलाके में ब्रेस ब्रिज के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत ढ हने से बड़ा हादसा हो गया। बुधवार को तीन मंजिला निर्माणाधीन चाय गोदाम की तीसरी मंजिल की छत की ढ लाई के दौरान अचानक ढ ांचा भरभराकर गिर पड़ा। मलबे के नीचे कई मजदूर दब गए। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि अब तक 18 घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

- **निर्माणाधीन चाय गोदाम की तीसरी मंजिल की छत डल रही थी, जब पूरा ढांचा अचानक भरभरा कर गिर गया।**

घटना के बाद सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, कोलकाता पुलिस, अग्निशमन विभाग और कोलकाता नगर निगम की संयुक्त टीमें युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। मलबे में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द बाहर निकालने के लिए गैस कटर, क्रेन, एंबुलेंस और अन्य आधुनिक बचाव उपकरणों की मदद ली जा रही है। घटनास्थल से दबे हुए मजदूरों की आवाजें सुनाई देने की भी सूचना है। बचावकर्मी बाहर से उनके नाम पुकारकर उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बंदरगाह की जमीन पर उक्त चाय गोदाम का निर्माण किया जा रहा था। छत ढ हने के समय बड़ी संख्या में मजदूर वहां कार्यरत थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने 30 से अधिक मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई है, हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

संसद का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिवसेना (यूबीटी) के पास संसद में अपना पार्टी ऑफिस नहीं होगा। आमतौर पर संसद भवन में उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को ऑफिस की जगह दी जाती है, जिनके पास पांच या उससे ज्यादा सांसद होते हैं। शिवसेना (यूबीटी) के पास केवल चार सांसद होने की वजह से उनसे पार्टी ऑफिस लिया जा सकता है। इसके साथ ही, अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में शिवसेना (यूबीटी) की भागीदारी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पांच से कम सांसदों वाली पार्टियों को आम तौर पर ऐसी बैठकों में नहीं बुलाया जाता है। संसद के भीतर राजनीतिक दलों को ऑफिस की जगह आवंटित करने वाला कोई तय कानूनी नियम नहीं है। इसके बजाय, यह लंबे समय से चली आ रही संसदीय परंपराओं, दिशानिर्देशों और हाउस कमेटी की कार्यप्रणाली पर आधारित है।

नौ दिन देर से मानसून मध्य प्रदेश पहुँचा

- **यूपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा व दिल्ली में प्री-मानसून वर्षा का दौर जारी**

नई दिल्ली, 24 जून। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण-पश्चिम मानसून बुधवार को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया। मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर मानसून के आगमन की घोषणा करते हुए बताया कि यह बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी के रास्ते प्रदेश में पहुंचा है। इस बार मानसून सामान्य तिथि 15 जून के मुकाबले नौ दिन की देरी से आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेगा। मानसून के प्रवेश के साथ ही, बैतूल और बुरहानपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है।

मानसून की एंट्री के साथ मौसम विभाग ने भोपाल सहित, 42 जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, खरगोन, बड़वानी, आलीराजपुर, हरदा, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, सिवनी, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज और अन्य जिलों में मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है। देश के 6 राज्यों-उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री-मानसून बारिश जारी है। मंगलवार को बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश में पहुंच सकता है।

ममता बनर्जी अपनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी। उस समय शुभेन्दु अधिकारी ने ही मुझे संभाला और भरोसा दिलाया था।"

तृणमूल कांग्रेस की तेजतर्रार नेता महुआ मोइत्रा ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत करीमपुर से की थी, जहां उन्होंने 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने बताया कि उस समय वे राजनीति में नई थीं और कोई भी वरिष्ठ तृणमूल नेता उनके लिए प्रचार करने नहीं आया था। लेकिन, शुभेन्दु अधिकारी उनकी पहली चुनावी रैली में मौजूद थे।

उन्होंने कहा, "जब मैंने पहली बार करीमपुर से चुनाव लड़ा था, तब मेरे लिए प्रचार करने कोई नहीं आया था। मेरी पहली रैली शुभेन्दु अधिकारी ने की थी। आज भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहां सिर्फ मैं और शुभेन्दु अधिकारी थे।"

शुभेन्दु अधिकारी ने 2020 में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव को लेकर पैदा हुए मतभेदों के बाद, तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए और इस वर्ष बंगाल चुनाव में पार्टी को निर्णायक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि अब उनकी शुभेन्दु अधिकारी से पहले जैसी बातचीत नहीं होती, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत रिश्ते राजनीतिक सीमाओं से ऊपर होते हैं।

उन्होंने कहा, "आज शुभेन्दु किसी दूसरी पार्टी में हैं, इसलिए अब हमारी बातचीत नहीं होती। लेकिन उन्होंने जो मदद मुझे दी थी, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती।"

यह बयान ऐसे समय आया है, जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। महुआ मोइत्रा को ममता ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में शामिल किया था।

दूसरी ओर, बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया है। उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग का भी रुख किया है।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिशन प्रमुखों को भेजे गए उपहार में आम की चार प्रमुख किस्में- केसर, दशहरी, बंगनपल्ली और लंगड़ा शामिल हैं। इसके साथ एक व्यक्तिगत संदेश भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आम अपने क्षेत्र की विशेष पहचान, स्वाद और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहल भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को दर्शाती है और दुनिया के साथ भारतीय संस्कृति के सौहार्द और मिठास को साझा करने का एक प्रयास है।

मेयर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। साथ ही, नालों में फंसे कचरे को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "बृहन्मुंबई महानगरपालिका युद्धस्तर पर काम कर रही है।" इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुशासन के बजाय, राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रही है। ज्ञातव्य है कि महायुति गठबन्धन में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट भी शामिल है, जिसने ठाकरे गुट के छह सांसदों को अपने साथ कर लिया था। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने "बीएमसी का सारा फंड खत्म कर दिया है।" उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने पिछली सरकार, यानी ठाकरे-नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार की सलाह के बावजूद, बारिश का पानी जमा करने वाले टैंक नहीं बनवाए।

केदारनाथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब तक कुल 13,21,067 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है।

केन्द्रीय सरकार को अगूँठा दिखाने की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य पर लगभग 8.15 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज था। फिलहाल राज्य के पास इस कर्ज के बोझ को सार्थक ढंग से कम करने की बहुत कम गुंजाइश है। यह कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 40 प्रतिशत है।

राज्य की वित्तीय स्थिति असल में एक "डैथ ट्रैप" में फंस गई है, जिसे "ऋण जाल" कहा जाता है। यानी, राज्य पुराने कर्ज और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए नया कर्ज ले रहा है। अनुमानत: राज्य को हर वर्ष एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि पुराने कर्ज और ब्याज के भुगतान में खर्च करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त उधारी का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है, न कि ऐसे निवेशों में, जो राज्य की आय बढ़ा सकें।

इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि बेकार चीजों पर सब्सिडी और अनुदानों का बोझ लगातार बढ़ता गया। इस तरह, जो कम फंड मौजूद थे, उनमें से भी, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करने के बजाय, इमाम भत्ता, पुजारी भत्ता और दुर्गा पूजा क्लबों को अनुदान जैसी योजनाओं पर खर्च किया गया। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति कमज़ोर होती चली गई और अब उसके पुनर्गठन की आवश्यकता है।

तथापि, वित्त मंत्री के पास इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर अभी शुरू करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इसलिए यह बजट, फिस्कल स्ट्रक्चर और सरकारी फायनैंस को लंबे समय तक रीस्ट्रक्चर करने की शुरुआत के बजाय एक होल्डिंग ऑपरेशन है।

भाजपा सरकार राज्य कर्मचारियों और सरकार के बीच महंगाई भत्ते के पेमैंट को लेकर लंबे समय से चल रही लड़ाई के बाद सत्ता में आई। राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की तुलना में काफी कम डीए मिल रहा था। यह संघर्ष समय के साथ अधिक तीखा होता गया।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने डीए की मांग कर रहे कर्मचारियों की तुलना "भौंकते कुत्तों" से कर दी। इससे कर्मचारियों को केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने स्वयं को अपमानित भी महसूस किया।

मुख्यमंत्री ने आंदोलनरत कर्मचारियों से वादा किया था कि यदि वे सत्ता में आए तो इस मुद्दे पर फैसला करते समय वे उनके साथ "सम्मानजनक व्यवहार" करेंगे।

अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। बजट में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जिसने आंदोलनरत कर्मचारियों की अपेक्षाओं को भी पीछे छोड़ दिया। निश्चित रूप से वर्तमान वित्तीय स्थिति इतनी उदारता की अनुमति नहीं देती, लेकिन सरकार के पास शायद कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था।

इसी प्रकार भाजपा ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की सहायता देने का वादा किया था। तृणमूल सरकार अपनी योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये देती थी। शुरुआत में इस योजना से महिलाओं के बीच पार्टी को समर्थन मिला था, लेकिन भाजपा ने इसकी दोगुनी राशि देने का वादा कर बढ़त बना ली। बजट में पात्र महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है।

सकारात्मक बात यह है कि पुरानी योजना का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था। सत्ता में आने के बाद नई सरकार ने पाया कि बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि कई पुरुष महिलाओं के लिए निर्धारित इस सहायता राशि को अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे थे। यह कैसे संभव हुआ, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है।

कुछ अनुदानों में कटौती की गई है, जबकि कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। हालांकि वित्त मंत्री और नई सरकार ने इनका बोझ कम करने के लिए इन्हें विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं से जोड़ने की रणनीति अपनाई है। पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार ने केन्द्र के प्रति विरोध के कारण कई केन्द्रीय योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया था। यह वैसा ही था, जैसे किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना।

राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को केन्द्र की योजनाओं के साथ जोड़कर बजट ने फंडिंग का बोझ केन्द्रीय स्कीमों पर डालकर राज्य के फायनैंस पर उनके असर को कम करने की कोशिश की है। तथाकथित "डबल इंजन सरकार" मॉडल के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि केन्द्र पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएगा।

मुफ्त योजनाओं और अनुदानों की चर्चा से अलग हटकर देखें तो नई सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं, जिन्हें दीर्घकालिक महत्व का माना जा सकता है। इनमें से कई कदम बजट से बाहर के हैं, लेकिन भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

ऐसी ही एक घोषणा यह है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए निवेशकों को नगर निकायों और जिला स्तर की अनेक अनुमतियों के लिए अलग-अलग चक्कर नहीं लगाने होंगे। उच्च स्तर से स्वीकृति मिलते ही अन्य आवश्यक अनुमतियां स्वत: स्वीकृत मानी जाएंगी। यह बड़े निवेशों के लिए एकल-खिड़की मंजूरी (सिंगल विंडो क्लियरैंस) प्रणाली की तरह है।

केन्द्र की नीतियों के अनुरूप राज्य ने विभिन्न स्थानों पर कम से कम चार नए हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इनका वित्त-पोषण छोटे हवाई अड्डों और राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तर बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार का भी प्रस्ताव है।

बंगाल के तटीय क्षेत्र में कांदी जिले में एक बड़े समुद्री बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव है। राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर उत्तर बंगाल के जिलों में, एम्स जैसे कई चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की भी योजना है। नई सरकार पर्यटन विकास के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में राज्य के पास अपार संभावनाएं हैं।

क्षेत्रों को बेहतर ढंग से जोड़ने और लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए बड़ी और छोटी सड़कों के विस्तृत नेटवर्क के निर्माण का भी प्रस्ताव है। ऐसे निवेशों का अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा और कई गुना असर पड़ सकता है।

हालांकि भाजपा का यह पहला बजट अनेक सीमाओं से घिरा हुआ है, फिर भी इसमें नई सरकार की ओर से कुछ आशाजनक कदम दिखाई देते हैं। सबसे सुखद बात यह है कि लगभग पचास वर्षों के बाद राज्य सरकार औद्योगीकरण और विकास की एक नई शुरुआत की ओर देखती नज़र आ रही है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908